

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 9 मार्च, 2006/18 फालान, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 9 मार्च, 2006

संख्या वि० स0-विधायन-गवर्न.बिल. 1-18/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 9 मार्च, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित 7728 असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2006/18 फाल्गुन, 1927 हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हरताक्षरित / -(जे0 आर0 गाज़टा) सचिव. हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2006 का विधेयक संख्यांक 4

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान समा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संक्षेप्त संशोधन) अधिनियम, 2006 है। विस्तार और
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

प्रारम्भ ।

- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता की धारा 289 1860 के के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— केन्द्रीय अधिनयम

संख्यांक

45 का

रांशोधन ।

- "289—क. लोक स्थान में बंदरों को खिलाना.— जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित से अन्यथा लोक स्थान में खाद्य वस्तुएं फैंकेगा और तद्द्वारा बन्दरों को खाद्य पदार्थों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामरवरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनता या जनसाधारण को क्षति या क्षोभ कारित होना सम्भाव्य हो या यानीय यातायात के निर्बाध आवागमन में प्रतिबाधा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"।
- 3. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक "**I मारतीय** ^{1974 के} दण्ड संहिता के अधीन अपराध" के अधीन, धारा 289 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के ^{केन्द्रीय} अधि^{नियम}

असाधारण राजपञ्ज हिमाचल प्रदेश, ६ मार्ग, २००६/ १८ फाल्युन, १९२७ पश्चात् निम्नलिखित प्रविधिया अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

1	2	3	4	6	()
"289 · b	जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में आधर्मृषित से अन्यथा लोक स्थानो में खाद्य वस्तुएं फैंकेमा और तद्धारा बदरों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकद्दता होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनत या जनसाधारण को हार्ति सा सोभ कारित होन सालायात के निर्हा आवागमन में प्रतिबाह कारित हो	एक मारा के लिए कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों । । । । ।		यशीवत	यथोवत ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 की सिविल रिट याधिका संख्या 883 नामतः कंबर रतनीत सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य, लिखत है। तारीख 20 7 2004 के अन्तरिम प्रादेश में माननीय उच्च न्यायालय ने सन्य सरकार को निदेश दिए हैं कि वह भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने के साथ साथ विशेष विशेष अधिनियमित करने हेतु विधान लाने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करें। अत माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों की अनुपालना करने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १७७३ में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता, १७७३ में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्वि के लिए है।

वीरगद सिंह, गुरुष मन्त्री।

शिमला	•	
ताशैख		2006.

वित्तीय ज्ञापन

- शुन्य

प्रत्यायोजिल विधान सम्बन्धी ज्ञापन

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मार्च, 2006 / 18 फाल्गुन, 1927 दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

> वीरमद सिंह. मुख्य मंत्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला	:	
तारीख		2006

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT)

Bill No. 4 of 2006.

HE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

BILL.

further to amend the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No.2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fiftyseventh Year of the Republic of India, as follows:-

- (1) This Act may be called the Criminal Law (Himachal Pradesh Short title, extent and Amendment) Act, 2006. commencement.
 - (2)It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.
 - (3) It shall come into force at once.
- After section 289 of the Indian Penal Code, in its application to the State Amendment of Central of Himachal Pradesh, the following section shall be added, namely: Act No.45 of 1860.
 - "289-A. Feeding of Monkeys in public place. -- Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.".
- 3. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, 1973, under the Amendment heading "I. OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", after the entries of Central

7734		असाधारण राजपत्र,	हिमाचल प्रदेश, ७ माच	i, 2006/	१८ फाल्गु	्न, 1927	
	relating to s	ection 289, the following	ng entries shall be in	serted, na	mely:-	_	
	1	2	3	4	5	6	
	"289-A.	Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic		Ditto	Ditto	Ditto.".	

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A civil writ petition No.653 of 2003—titled as Kanwar Rattanjit Singh Versus Union of India and others is pending in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh. In the interim order dated 29-7-2004, the Hon'ble High Court has directed the State Government to take immediate necessary action to bring a legislation both with respect to the amendment in the Indian Penal Code as well as enacting a special law. Thus, in order to comply with the directions of the Hon'ble High Court, it has been decided to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1973 in their application to the State of Himachal Pradesh. This has necessitated the amendments in the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure, 1973.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2006

Α

BILL

further to amend the Indian Penal Code (Act No.45 of 1860) and the Code of Criminal Procedur., 2 1973 (Act No.2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh.

VIRBHADRA SINGH, Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR, Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The2006.